समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम		जवाहर रोजगार योजना
	सहायता किए गए परिवारों की संख्या	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)
1994-95	22701	24-36
1995-96	11786	6.44 (अक्तूबर 1995 तक)

Amnesty International Reports of India

26. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government had received any report of Amnesty International pertaining to India; and

(b) if so, the salient features thereof and the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I.K. GUJRAL): (a) Yes, Sir.

(b) Amnesty International brings out a report every year on the human rights situation in various countries. The 1995 report includes a section on India which, inter alia, includes a range of general allegations of human rights violations, in Jammu & Kashmir and Punjab. Government of India examines and responds to all Amnesty International reports.

Upgradation of State Highways to National Highways in Andhra Pradesh

27. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the State Government of Andhra Pradesh had submitted 9 proposals covering a length of 4,812 k.m. to the Union Ministry vide letter No. 1612 (R11) (2)/91-3 Dt: 24.2.1992 for upgradation of state highways to National Highways;

(b) if so, whether out of these proposals, Government of India sanctioned state highways from Kurnool to Chitoor to a length of 362 kms as N+18 in January 1993;

(c) the fate of the other proposals;

(d) to what extent the work on the approved highways have been completed; and

(e) by when all proposals are likely to be accepted and work on these is likely to be started?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Owing to limited availability of funds for the development of National Highways during the 8th Plan, it has not been possible to accept the proposals.

(d) Improvement of National Highways is a continues process and on N+18, improvement works aggregating to Rs. 7.2 crores have been sanctioned since its declaration and are at various stages of progress.

(e) In view of (c) above, it is difficult to indicate a time frame.

Improving Indo-Pak Relations

28. SHRI JANARDHANA POOJARY:
SHRIMATI JAYANTI PATNAIK:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to improve Indo-Pak relations by holding Secretary/Minister level talks with Pakistan;

(b) if so, the proposal mooted by Government in this regard;

(c) the suggestions that have come from the Pakistan Government in this regard; and

(d) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I.K. GUJRAL): (a) to (d) Government is very keen to improve India-Pakistan relations.

In her message of felicitations to our Prime Minister on his assumption of office, Her Excellency, the Prime Minister of Pakistan urged that India and Pakistan should sit across the table in a search for lasting peace. In his reply, dated June 8, 1996, the Prime Minister of India has suggested that the two countries undertake a wide-raging and comprehensive dialogue and resume the Foreign Secretary level talks. PM underlined that bilateral approaches and agreements, which have been devised earlier, could guide future exchanges on all matters, including those on which the two countries might have differing perceptions. PM also emphasised that efforts should be directed towards pulling down the barriers which have made people-to-people interaction between the two countries difficult and to encourage the promotion of trade, economic and cultural contacts.

Pakistan's response to PM's letter to Prime Minister of Pakistan is awaited.

भूतपूर्व सैनिकों को प्रोत्साहन

29. **श्री अजीत जोगी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को लघु स्व-रोजगार परियोजनाएं आरंभ करने के लिए प्रोत्साहन दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के लिए दिए गए उक्त प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने-कितने भूतपूर्व सैनिक लाभान्वित हुए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): (क) से

(ग) लघु और मध्यम स्तर के उद्योग लगाने के इच्छुक भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों को वित्तीय तथा अन्य सहायता दिए जाने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं। महत्वपूर्ण स्वरोजगार योजनाएं इस प्रकार हैं:—

सेमफेक्स-1: अप्रैल 1987 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सहयोग से शुरू की गई इस योजना में भूतपूर्व सैनिकों, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों तथा अशक्त सैन्य कार्मिकों को लघु उद्योग इकाइयां, परिवहन उद्यम, सेवा उद्यम, होटल, नर्सिंग होम तथा पर्यटन परियोजनाएं स्थापित किए जाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। इस योजना के अंतर्गत 15 प्रतिशत साफ्ट सीड सहायता सहित 15 लाख रुपए तक ऋण दिया जाता है। साफ्ट सीड सहायता पर ऋण की दर केवल 6 प्रतिशत है। आवधिक ऋणों पर ब्याज की दर भारतीय रिजर्व बैंक से समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार वसूल की जाती है।

सेमफेक्स-2: यह योजना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से जनवरी 1988 में शुरू की गई थी। इस योजना में कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों या ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि इकाइयां स्थापित करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को प्रोत्साहित करने के वास्ते ऋण उपायों के व्यापक पैकेज की व्यवस्था शामिल की गई है। फार्म क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय सहायता/ऋण के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। गैर-फार्म क्षेत्र में समेकित ऋण योजना के अन्तर्गत कृषि, गैर-कृषि उद्योग तथा सेवा उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए की बैंक ऋण की उच्चतम सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण में आवधिक ऋण है और इसमें प्रोत्साहकों के योगदान का कतिपय प्रतिशत शामिल है आवधिक ऋण पर ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार लगाया जाता है। फार्म क्षेत्र के संबंध में प्रोत्साहकों का योगदान अर्थात् अतिरिक्त धनराशि जो छोटे किसानों के लिए 5 प्रतिशत, मध्यम स्तर के किसानों के लिए 10 प्रतिशत, अन्य किसानों के लिए 15 प्रतिशत और कृषि संसाधित इकाइयां के लिए 25 प्रतिशत है। सामान्यतः, गैर-फार्म